Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

08 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. भारत और रूस ने इंजीनियरिंग, नवाचार और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय औद्योगिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

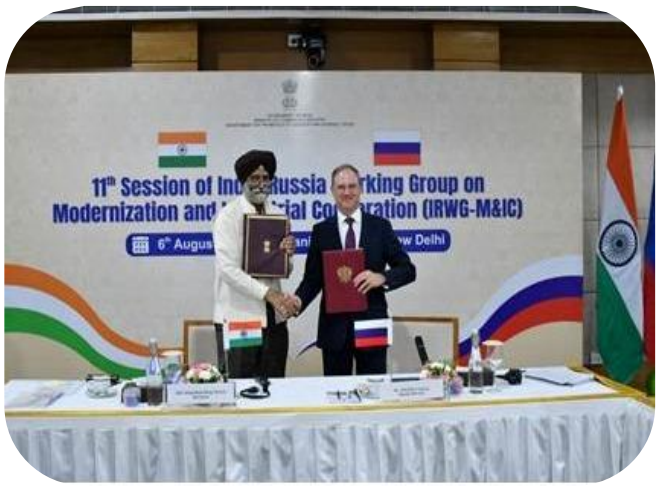

6 अगस्त, 2025 को भारत और रूस ने औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के उद्देश्य से एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह के 11वें सत्र के दौरान औपचारिक रूप दिया गया।

• इस प्रोटोकॉल पर व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के ढांचे के तहत हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय औद्योगिक और तकनीकी संबंधों की पुष्टि और विस्तार पर केंद्रित था।

• भारत की ओर से इस समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने हस्ताक्षर किए। रूस का प्रतिनिधित्व रूसी संघ के उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री एलेक्सी ग्रुज़देव ने किया।

• प्रोटोकॉल का उद्देश्य एल्युमीनियम, उर्वरक, रेलवे परिवहन, खनन क्षेत्र प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इंजीनियरिंग उपकरण और औद्योगिक/घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे औद्योगिक क्षमता और नवाचार में वृद्धि होगी।

Key Points:-

(i) इस सहयोग में एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी, आधुनिक पवन और छोटे विमान इंजन, कार्बन फाइबर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3डी प्रिंटिंग, दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज और निष्कर्षण, भूमिगत कोयला गैसीकरण और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।

(ii) इस सत्र में दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे।

2. गुजरात ने वित्त वर्ष 2025 में 9.83 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ भारत के निर्यात में शीर्ष स्थान बरकरार रखा।

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (FIEO) ने राज्यों के निर्यात 2024-25 का अवलोकन जारी किया है, जिसमें गुजरात को भारत का अग्रणी निर्यातक बताया गया है, जो 9.83 लाख करोड़ रुपये मूल्य के शिपमेंट

के साथ देश के कुल निर्यात में एक-चौथाई से अधिक का योगदान देता है।

• वित्त वर्ष 2025 में गुजरात का निर्यात प्रदर्शन ₹9.83 लाख करोड़ रहा, जो भारत के कुल निर्यात का 26.6% था। यह उपलब्धि व्यापार में राज्य के प्रभुत्व को पुख्ता करती है, जो मज़बूत औद्योगिक क्षमता और प्रमुख क्षेत्रों में विविध उत्पाद पोर्टफोलियो द्वारा संचालित है।

• वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया सहित शीर्ष देशों को निर्यात करता है, जो विभिन्न उद्योगों में राज्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

• भारत द्वारा निर्यात की गई 169 वस्तुओं में से, गुजरात ने 158 वस्तुओं का निर्यात किया, जो इसके व्यापक औद्योगिक आधार को दर्शाता है। प्रमुख निर्यात श्रेणियों में पेट्रोलियम उत्पाद (37.72%), सूती कपड़े, चीनी मिट्टी की चीज़ें, रसायन, प्लास्टिक और रत्न एवं आभूषण शामिल थे, जो राज्य की मज़बूत और विविध विनिर्माण क्षमता का संकेत देते हैं।

Key Points:-

(i) जामनगर जिला गुजरात का अग्रणी निर्यात केंद्र बनकर उभरा है, जिसने राज्य के कुल निर्यात में ₹3.63 लाख करोड़ (36.91%) का योगदान दिया है। यह प्रभुत्व मुख्यतः इसकी विशाल पेट्रोलियम शोधन क्षमता और थोक निर्यात को समर्थन देने वाले मज़बूत लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे के कारण है।

(ii) शीर्ष पांच निर्यातक राज्यों - गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश - ने सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल निर्यात में लगभग 71% का योगदान दिया, जिसका संयुक्त मूल्य विभिन्न क्षेत्रों और उत्पाद श्रेणियों में लगभग 27.07 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

(iii) FIEO की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024 के 134.39 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुजरात के निर्यात मूल्य में मामूली गिरावट को दर्शाया गया है। इसके बावजूद, राज्य ने अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है, जो अस्थिर माँग, भू-राजनीतिक चुनौतियों और बदलते बाज़ार रुझानों के बावजूद वैश्विक व्यापार में लचीलेपन को दर्शाता है।

3. अरुणाचल प्रदेश की कबाक यानो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बन गईं।

4 अगस्त, 2025 को अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही कबाक यानो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के शिखर पर चढ़ गए, जो उनके चल रहे सात शिखर अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

• 5,895 मीटर ऊँचा माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत और दुनिया की सबसे ऊँची स्वतंत्र चोटी, दोनों है। कबक यानो की सफल चढ़ाई, सात महाद्वीपों के सबसे ऊँचे पर्वतों—सेवन समिट्स—को फतह करने के उनके महत्वाकांक्षी मिशन में योगदान देती है।

• मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले की रहने वाली कबाक यानो को मई 2024 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए देशव्यापी मान्यता मिली, जिससे वह अपने राज्य की पांचवीं महिला और ऐसा करने वाली न्यिशी समुदाय की पहली महिला बन गईं।

Key Points:-

(i) इस अभियान को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) के. टी. परनाइक ने 28 जुलाई को राजभवन, ईटानगर से आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यानो की सफलता की खबर सुनकर, उन्होंने यानो के साहस और अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को प्रेरित करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा, "दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प के साथ, कोई भी शिखर असंभव नहीं है।"

(ii) मात्र 26 वर्ष की आयु में, यानो की उपलब्धि पर्वतारोहण से कहीं आगे तक गूंजती रही—यह साहस, दृढ़ता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। उनकी यात्रा साहसिक गतिविधियों के शौकीनों और पूर्वोत्तर की महिलाओं को कठिन रास्तों पर अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती रहती है।

4. MOSPI ने संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए GDP, IIP और CPI के लिए नए आधार वर्ष का प्रस्ताव दिया है।

6 अगस्त 2025 को, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के लिए आधार वर्षों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत इस प्रस्ताव का उद्देश्य अद्यतन पद्धतियों और आँकड़ों के स्रोतों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरते ढाँचे को बेहतर ढंग से समझना है।

• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने GDP और IIP गणनाओं के लिए आधार वर्ष को 2022-23 तक अद्यतन करने का सुझाव दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये सूचकांक वर्तमान औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करें। CPI के लिए, आधार वर्ष 2024 प्रस्तावित है, ताकि मुद्रास्फीति माप को देश में नवीनतम उपभोग पैटर्न के साथ संरेखित किया जा सके।

• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में संशोधन में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 से प्राप्त अद्यतन मद सूची और संबंधित भारांक शामिल किए जाएँगे। इससे ग्रामीण और शहरी भारत में उपभोक्ता व्यय आदतों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए खुदरा मुद्रास्फीति माप की सटीकता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

• आधार वर्ष बदलने का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों को शामिल करना है, जैसे कि प्रौद्योगिकी में प्रगति, सेवाओं का विस्तार और औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन। इसका उद्देश्य वैश्विक सांख्यिकीय प्रथाओं के साथ संरेखण में सुधार करना और आर्थिक विकास एवं मुद्रास्फीति के रुझानों का अधिक यथार्थवादी आकलन प्रदान करना भी है।

Key Points:-

(i) नवंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में पूंजीगत व्यय (CAPEX) के इरादों पर अपना पहला भविष्यदर्शी सर्वेक्षण किया। बाद में प्रकाशित निष्कर्ष भविष्य के निवेश रुझानों और भारत के आर्थिक विस्तार को गति देने वाले संभावित क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने निगमित सेवा क्षेत्र के आँकड़े एकत्र करने के लिए सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASSSE) पर एक पायलट अध्ययन किया। यह भारत के तेज़ी से बढ़ते सेवा उद्योग के आर्थिक योगदान को और अधिक सटीकता से मापने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(iii) प्रस्तावों और सर्वेक्षण के निष्कर्षों को लोकसभा में राव इंद्रजीत सिंह द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के साथ-साथ संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं। यह घोषणा डेटा-आधारित नीति निर्माण पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाती है।

INTERNATIONAL

1. Illinois ने मनोवैज्ञानिक संसाधनों के लिए ऐतिहासिक कल्याण और निरीक्षण अधिनियम के तहत AI को चिकित्सा प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

4 अगस्त, 2025 को इलिनोइस के गवर्नर जे.बी. प्रित्जकर ने मनोवैज्ञानिक संसाधनों के लिए कल्याण और निरीक्षण (WOPR) अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मानव पर्यवेक्षण के बिना स्वतंत्र चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य निर्णय लेने के लिए चैटजीपीटी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्लेटफार्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

• WOPR अधिनियम, कृत्रिम बुद्धि (AI) को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने, उपचार योजनाएँ बनाने, या चिकित्सीय बातचीत में शामिल होने से रोकता है, जब तक कि कोई लाइसेंस प्राप्त व्यवहारिक स्वास्थ्य पेशेवर इसकी देखरेख न करे। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य चिकित्सक ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करें।

• AI उपकरणों का उपयोग प्रशासनिक और पूरक भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है, जैसे कि समय-निर्धारण, बिलिंग, बीमा प्रसंस्करण और गैर-नैदानिक संचार का मसौदा तैयार करना - जब तक कि लाइसेंस प्राप्त विशेषज्ञ सामग्री के लिए पूरी जिम्मेदारी बरकरार रखता है।

• इस कानून का उद्देश्य बच्चों सहित असुरक्षित व्यक्तियों को अनियमित AI सलाह से बचाना और

प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की नौकरियों की रक्षा करना है। उल्लंघन करने पर प्रति अपराध 10,000 अमेरिकी डॉलर तक का नागरिक जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे इलिनोइस वित्तीय एवं व्यावसायिक विनियमन विभाग (IDFPR) द्वारा लागू किया जाएगा।

Key Points:-

(i) विधायकों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि AI में सहानुभूति, प्रासंगिक समझ और जवाबदेही का अभाव है—जो प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रमुख तत्व हैं। चिंता उन मामलों से उत्पन्न हुई जहाँ AI चैटबॉट्स ने आत्म-क्षति या मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को बढ़ावा देने सहित भयावह सलाह दी।

(ii) इलिनॉय चिकित्सीय सेवाओं में AI के उपयोग को विशेष रूप से विनियमित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। यह यूटा और नेवादा जैसे राज्यों में इसी तरह के, लेकिन कम प्रतिबंधात्मक कदमों के बाद आया है, और स्वास्थ्य सेवा में AI पर आगामी संघीय और कानूनी नियमों से पहले आया है।

(iii) WOPR अधिनियम नवाचार और नैतिक देखभाल के बीच संतुलन बनाने में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। हालाँकि विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में AI की क्षमता को पहचानते हैं, यह कानून स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करता है और पुष्टि करता है कि AI सशक्त तो हो सकता है, लेकिन मानव चिकित्सकों की जगह नहीं ले सकता।

BANKING & FINANCE

1. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंक ट्रांजिशन के लिए RBI की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला SFB बनकर इतिहास रच दिया।

7 अगस्त, 2025 को, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU SFB) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। इस तरह, यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) बन जाएगा। पिछली ऐसी मंजूरी बंधन बैंक को 2015 में मिली थी।

- **यह परिवर्तन RBI के स्वैच्छिक रूपांतरण ढांचे और अप्रैल 2024 में जारी "ऑन-टैप" लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों का पालन करता है। AU ने सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया, जिसमें संतोषजनक प्रदर्शन का पांच साल का ट्रैक रिकॉर्ड, पर्याप्त निवल मूल्य (₹10 बिलियन), पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का निम्न स्तर शामिल है।**

- **सार्वभौमिक बैंक का दर्जा मिलने के बाद, एयू अब खुदरा बैंकिंग से आगे बढ़कर बड़े कॉर्पोरेट ऋण उपलब्ध करा सकता है, सहायक कंपनियां शुरू कर सकता है, धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर सकता है, विदेशी मुद्रा परिचालन में प्रवेश कर सकता है, तथा एक समेकित छतरी के नीचे अपने डिजिटल बैंकिंग समाधानों को व्यापक बना सकता है।**

- **यह सैद्धांतिक मंजूरी RBI द्वारा लगभग दस वर्षों में दिया गया पहला पूर्ण सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस है। पिछली मंजूरी 2015 में बंधन बैंक और IDFC (अब IDFC फर्स्ट बैंक) को दी गई थी।**

Key Points:-

(i) RBI के निर्देशों के अनुसार, AU के प्रमोटर संजय अग्रवाल अगले 18 महीनों के भीतर अपनी पूरी 22% इक्विटी हिस्सेदारी एक नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (NOFHC) में स्थानांतरित कर देंगे। इसके अतिरिक्त, बैंक अपना कॉर्पोरेट मुख्यालय जयपुर से मुंबई स्थानांतरित कर देगा।

(ii) वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में, AU ने साल-दर-साल 16% की वृद्धि के साथ ₹580.9 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, साथ ही ₹1 लाख करोड़ से ज़्यादा के बढ़ते ऋण पोर्टफोलियो और मज़बूत खुदरा संचालन की भी जानकारी दी। बाज़ार की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही-RBI की घोषणा के बाद AU के शेयरों में इंट्राडे में लगभग उत्साह को दर्शाता है। 48% की बढ़ोतरी हुई, जो निवेशकों के

2. RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को 5.50% पर स्थिर रखा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 56वीं बैठक 4 से 6 अगस्त, 2025 तक आयोजित की। MPC ने तटस्थ रुख बनाए रखते हुए नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

• मौद्रिक नीति समिति MPC की तीसरी द्विमासिक बैठक 4 से 6 अगस्त, 2025 तक तीन दिनों तक चली, जिसमें गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा, डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और डॉ. राजीव रंजन सहित सभी छह सदस्यों ने भाग लिया। MPC के गठन के बाद से यह 56वीं बैठक थी।

• MPC ने सर्वसम्मति से चलनिधि समायोजन सुविधा LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.50% पर बनाए रखने के लिए मतदान किया। इस निर्णय के तहत स्थायी जमा सुविधा SDF की दर 5.25% पर अपरिवर्तित, सीमांत स्थायी सुविधा MSF की दर 5.75% पर स्थिर और बैंक दर 5.75% पर स्थिर रखी गई।

• समिति का तटस्थ रुख आर्थिक विकास को बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने पर उसके दोहरे फोकस को दर्शाता है। आरबीआई ने कहा कि अपरिवर्तित ब्याज दरें पहले किए गए मौद्रिक ढील उपायों का अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करेंगी।

Key Points:-

(i) यह निर्णय फरवरी 2025 में की गई 100 आधार अंकों bps की रेपो दर में कटौती के प्रभावों को ऋण दरों पर भी लागू करने की आवश्यकता से प्रेरित था। आरबीआई का मानना है कि इससे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) इस बैठक के बाद RBI की प्रमुख मौद्रिक नीति दरों में शामिल हैं: रेपो दर -5.50%, रिवर्स रेपो दर - 3.35%, स्थायी जमा सुविधा (SDF) -5.25%, सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) - 5.75%, बैंक दर - 5.75%, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) - 3.00%, और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) 18.00%।

(iii) इस बैठक का परिणाम उधारकर्ताओं, निवेशकों और बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच नीतिगत स्थिरता का संकेत देता है। यह मुद्रास्फीति प्रबंधन और आर्थिक विस्तार के बीच संतुलन बनाने के लिए आरबीआई के सतर्क दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है।

3. RBI ने जोखिम साझाकरण और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए अंतिम सह-ऋण मानदंड जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पारदर्शिता बढ़ाने और संतुलित जोखिम-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के बीच सह-ऋण के लिए अंतिम संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। अगस्त 2025 में जारी किए गए ये अद्यतन मानदंड 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे।

• संशोधित मानदंडों के अनुसार, सह-ऋण व्यवस्था CLAS में संलग्न सभी विनियमित संस्थाओं REs के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण का कम से कम 10% अपनी बही में रखना अनिवार्य है। यह प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत कार्यरत सभी बैंकों और NBFCs पर लागू होता है।

• RBI ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल ऋण व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल ऋण) निर्देश, 2022 द्वारा शासित होती रहेगी। यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक और डिजिटल सह-ऋण मॉडल दोनों नियामक अनुपालन और उधारकर्ता संरक्षण मानकों को बनाए रखें।

• दिशानिर्देशों में एक सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसके तहत मूल ऋणदाता को ऋण की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर ऋण का हिस्सा सह-ऋणदाता को हस्तांतरित करना होगा। इसका उद्देश्य परिचालन में देरी को रोकना और ऋणदाता भागीदारों के बीच ऋण का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करना है।

Key Points:-

(i) नए नियमों के तहत, मूल ऋणदाता, ऋण वृद्धि को समर्थन देने के लिए, कुछ शर्तों के अधीन, बकाया ऋण पोर्टफोलियो के अधिकतम 5% की डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी DLG प्रदान कर सकते हैं। ये मानदंड लघु वित्त बैंकों SFB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RBI, स्थानीय क्षेत्र बैंकों LABs, वित्तीय संस्थानों और आवास वित्त कंपनियों HFC सहित सभी श्रेणियों की NBFC पर लागू होते हैं।

(ii) इन अंतिम रूप दिए गए सह-ऋण नियमों से जोखिम-साझाकरण तंत्र में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि, तथा अर्थव्यवस्था के वंचित क्षेत्रों तक ऋण पहुंच का विस्तार होने के साथ-साथ मजबूत नियामक निगरानी सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

4. IFC और HDFC कैपिटल ने भारत में हरित किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए 1 बिलियन डॉलर का "एच-ड्रीम" फंड लॉन्च किया।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड ने भारत में हरित और किफायती आवास के विकास में तेजी लाने के लिए संयुक्त रूप से 1 बिलियन डॉलर का "एच-ड्रीम" (आवास विकास और पर्यावरण अनुकूल किफायती बाजार) फंड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देते हुए देश की बढ़ती शहरी आवास मांग को पूरा करना है।

- **यह साझेदारी निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए पर्यावरण के अनुकूल घरों के निर्माण में सहायता के लिए समर्पित एक बड़े पैमाने पर वित्तपोषण मंच बनाने पर केंद्रित है। यह निधि भारत की प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास पहल के अनुरूप है और हरित-प्रमाणित परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध डेवलपर्स को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करेगी।**

- **यह पहल उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी जो मान्यता प्राप्त हरित भवन मानकों जैसे कि EDGE (उत्कृष्ट दक्षता के लिए डिजाइन में उत्कृष्टता), IGBC (भारतीय हरित भवन परिषद) और GRIHA (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग) का पालन करती हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और ऊर्जा खपत में कमी आएगी।**

- **इसका उद्देश्य लक्षित जनसंख्या वर्ग के लिए लागत को वहनीय रखते हुए जलवायु-लचीले आवास बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।**

Key Points:-

(i) 1 अरब डॉलर की इस राशि का वित्तपोषण IFC के निवेश, HDFC कैपिटल के अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड (H-CARE) और अन्य घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के माध्यम से किया जाएगा। यह फंड एक मिश्रित वित्त मॉडल के रूप में काम करेगा, जिसमें रियायती पूंजी को बाजार दर पर निवेश के साथ जोड़कर आवास परियोजनाओं को और अधिक व्यवहार्य बनाया जाएगा।

(ii) IFC के अनुसार, भारत में लगभग 2.9 करोड़ शहरी आवासों की कमी है, और इस मांग का 95% हिस्सा किफायती आवास क्षेत्र से आता है। इस क्षेत्र में हरित निर्माण को बढ़ावा देकर, इस पहल के दोहरे प्रभाव पड़ने की उम्मीद है—भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी और शहरी आबादी की तत्काल आवास आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा करना।

(iii) यह फंड जलवायु परिवर्तन और शहरी आवास की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक वित्तीय संस्थानों और भारतीय डेवलपर्स के बीच बढ़ते सहयोग को भी दर्शाता है। सतत वित्त में IFC की वैश्विक विशेषज्ञता और HDFC कैपिटल की बाजार में गहरी उपस्थिति का लाभ उठाकर, यह पहल अगले दशक में भारत के आवास परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है।

ECONOMY & BUSINESS

1. अमेज़न इंडिया और FIEO ने MSMEs के ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

6 अगस्त 2025 को, अमेज़न इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) ने नीति समर्थन, प्रशिक्षण और वैश्विक बाजार पहुंच के माध्यम से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से ई-कॉमर्स निर्यात को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- **इस समझौता ज्ञापन पर फियो के महानिदेशक और CEO डॉ. अजय सहाय और अमेज़न इंडिया के सार्वजनिक नीति उपाध्यक्ष श्री चेतन कृष्णस्वामी ने हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर के साथ एक संयुक्त ई-कॉमर्स निर्यात कार्यबल का गठन हुआ जो MSME निर्यातकों के लिए एक नीति और बुनियादी ढाँचे का रोडमैप तैयार करेगा।**

- **इस साझेदारी का उद्देश्य 20 से ज़्यादा देशों में अमेज़न की मौजूदगी और FIEO के राष्ट्रव्यापी निर्यातक नेटवर्क का लाभ उठाकर MSMEs की वैश्विक बिक्री को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य क्षेत्रों में होम लिनेन, सजावट, पर्सनल केयर, स्वास्थ्य उत्पाद, परिधान, खिलौने, हस्तशिल्प, पैकेज्ड फ़ूड और होम टेक्सटाइल शामिल हैं।**

- **क्षमता निर्माण इस पहल का एक प्रमुख स्तंभ होगा। अमेज़न इंडिया और FIEO पूरे भारत में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि MSMEs को सीमा पार व्यापार आवश्यकताओं, अनुपालन प्रक्रियाओं और वैश्विक बाज़ारों के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को समझने में मदद मिल सके।**

Key Points:-

(i) सहयोग की योजना स्थानीय ऑफ़लाइन विक्रेता समुदायों की स्थापना करने की भी है ताकि सहकर्मी से सहकर्मी सीखने और रसद, भंडारण, अनुपालन सहायता और ऑनबोर्डिंग सेवाओं तक साझा पहुंच को सक्षम किया जा सके - जिससे छोटे व्यवसायों के लिए निर्यात प्रक्रिया अधिक सहज हो सके।

(ii) अमेज़न ने घोषणा की कि भारतीय ई-कॉमर्स निर्यात 2024 तक 13 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर चुका है, और कंपनी का लक्ष्य 2030 तक संचयी निर्यात में 80 बिलियन अमरीकी डॉलर सक्षम करना है। इस समझौता ज्ञापन को उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

(iii) एफआईईओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार की पहलों के अनुरूप है, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ई-कॉमर्स निर्यात हब कार्यक्रम भी शामिल है, ताकि वैश्विक स्तर पर "मेड इन इंडिया" उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके और एक मजबूत डिजिटल निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके।

2. भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 47% बढ़ा और इसका श्रेय मोबाइल फोन को जाता है।

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात साल-दर-साल 47% बढ़कर 12.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। यह उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से मोबाइल फोन शिपमेंट में 55% की वृद्धि के कारण हुई, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में देश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

• इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वृद्धि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन PLI योजना और मेक इन इंडिया कार्यक्रम जैसी पहलों की सफलता को दर्शाती है। इन नीतियों ने घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मज़बूत किया है, जिससे भारतीय कंपनियाँ उत्पादन बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय माँग को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हुई हैं।

• मोबाइल फ़ोन प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे, जिनका निर्यात वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में लगभग 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह 55% वृद्धि मोबाइल निर्माण में भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक बाज़ार में इसकी बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है।

• गैर-मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई, जो 37% बढ़कर 4.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। सौर मॉड्यूल, स्विचिंग और रूटिंग उपकरण, चार्जर एडेप्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने इस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पोर्टफोलियो में विविधता आई।

Key Points:-

(i) इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) का अनुमान है कि यह गति जारी रहेगी और वित्त वर्ष 26 के अंत तक कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 46-50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। यह अनुमान इस क्षेत्र की क्षमता और सहायक सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।

(ii) भविष्य की ओर देखते हुए, उद्योग जगत के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास में और अधिक निवेश, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में मूल्य संवर्धन बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दे रहे हैं। ये कदम वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और इस क्षेत्र में सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

3. गोल्डमैन Sachs ने अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के बीच कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया है।

अगस्त 2025 में, गोल्डमैन Sachs ग्रुप, इंक. ने भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमानों को कैलेंडर वर्ष 2025 (वर्ष 25) के लिए 6.5% और वर्ष 26 के लिए 6.4% तक कम कर दिया। यह संशोधन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी भारतीय आयातों पर 25% पारस्परिक शुल्क लगाने के बाद नए सिरे से व्यापार तनाव के बाद किया गया है।

• गोल्डमैन Sachs ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमान को 0.1 प्रतिशत अंक घटाकर 6.6% से 6.5% कर दिया, और कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए इसे 0.2 प्रतिशत अंक घटाकर 6.6% से 6.4% कर दिया। यह कमी अमेरिकी टैरिफ के बाद बढ़ी हुई व्यापार बाधाओं से होने वाले संभावित आर्थिक प्रभाव को दर्शाती है।

• GDP के साथ-साथ, वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म ने अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को भी समायोजित किया है। कैलेंडर वर्ष 2025 और वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) दोनों के लिए मुख्य मुद्रास्फीति 3.0% रहने का अनुमान है, जो पिछले अनुमानों की तुलना में 0.2 प्रतिशत अंकों की कमी दर्शाता है। यह व्यापार तनावों के बावजूद अपेक्षाकृत सौम्य मुद्रास्फीति के माहौल का संकेत देता है।

Key Points:-

(i) चालू खाता घाटा (CAD), जो एक प्रमुख बाह्य क्षेत्र संकेतक है, वर्ष 2025 और वर्ष 2026 दोनों के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% हो गया। CAD में यह वृद्धि व्यापार व्यवधानों और टैरिफ बाधाओं के भारत के बाह्य संतुलन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को दर्शाती है।

(ii) एक संबंधित घटनाक्रम में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 30 जुलाई, 2025 को रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया और वित्त वर्ष 26 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा। हालाँकि, इसने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति अनुमान को 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया, जो मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के गोल्डमैन सैक्स के दृष्टिकोण से कुछ हद तक मेल खाता है।

(iii) गोल्डमैन Sachs की यह समीक्षा वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच, जबकि मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण निकट भविष्य में अपेक्षाकृत स्थिर बने हुए हैं, उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। मुख्य ध्यान व्यापार तनावों और निर्यात एवं व्यापक आर्थिक स्थिरता पर उनके प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है।

MOUs and Agreement

1. अटल इनोवेशन मिशन ने भारत भर में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भाषिनी के साथ साझेदारी की।

7 अगस्त, 2025 को नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग - भाषिणी के साथ एक आशय पत्र (SoI) पर हस्ताक्षर किए - जिसका उद्देश्य पूरे भारत में स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देना और भाषा-समावेशी उद्यमिता को सुविधाजनक बनाना है।

• इस साझेदारी का उद्देश्य भाषिनी की भाषा प्रौद्योगिकियों को एआईएम के कार्यक्रमों में एकीकृत करके नवाचार तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे भाषा संबंधी बाधाएं समाप्त होंगी और विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाया जा सकेगा।

• प्रारंभिक कदम के रूप में, ज्ञान प्रसार को समर्थन देने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) अकादमी की सामग्री को भाषिनी के AI उपकरणों का उपयोग करके कई भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा।

• स्टार्टअप सहित AIM पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों को भाषिनी उपकरणों और सैंडबॉक्स वातावरण तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे बहुभाषी उत्पादों और सेवाओं का विकास संभव होगा।

Key Points:-

(i) AIM ने स्थानीय पहुंच और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए अपने मौजूदा नवाचार बुनियादी ढांचे - जैसे अटल इनक्यूबेशन सेंटर AICs अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र ACICs और नव लॉन्च किए गए भाषा समावेशी कार्यक्रम LIPI केंद्रों में भाषिनी प्लेटफार्मों को शामिल करने की योजना बनाई है।

(ii) AIM के मिशन निदेशक दीपक बागला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह सहयोग "भारत भर के नवप्रवर्तकों के लिए, चाहे वे किसी भी भाषा के हों, पहुँच और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है।" डिजिटल इंडिया भाषाई प्रभाग के सीईओ अमिताभ नाग ने कहा कि "भाषा कभी भी नवप्रवर्तन में बाधा नहीं बननी चाहिए।"

(iii) साझेदारी में एआई-संचालित अनुवाद उपकरण और एपीआई विकसित करना भी शामिल होगा, जिसे स्टार्टअप अपने उत्पादों में एकीकृत कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ई-गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए वास्तविक समय बहुभाषी समर्थन सक्षम हो सकेगा, जिससे समावेशिता और पहुंच बढ़ेगी।

AWARDS

1. जेन्सेन हुआंग फॉर्च्यून 2025 की "बिजनेस में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों" की सूची में शीर्ष पर; चार भारतीय मूल के CEO और 19 महिला नेताओं ने वैश्विक व्यापार प्रभाव को उजागर किया।

5 अगस्त, 2025 को, अमेरिकी वैश्विक व्यापार पत्रिका, फॉर्च्यून ने अपनी "फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिज़नेस लिस्ट" का दूसरा संस्करण जारी किया। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी NVIDIA के CEO और अध्यक्ष जेन्सन हुआंग इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 56वें स्थान पर हैं।

• इस सूची में भारतीय मूल की महिला और वर्टेक्स फार्मास्युटिकल्स की CEO डॉ. रेशमा केवलरमानी भी शामिल हैं, जिन्हें 62वां स्थान मिला है। इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में उनका यह पहला स्थान है, जो व्यापार जगत में भारतीय मूल के नेताओं के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।

• शीर्ष 10 शक्तिशाली व्यावसायिक नेताओं में, अल्फाबेट (गूगल की मूल कंपनी) के CEO सुंदर पिचाई, हुआवेई टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और CEO रेन झेंगफेई, ओपनएआई के CEO और सह-संस्थापक सैम ऑल्टमैन, जेपी मॉर्गन चेज़ के

अध्यक्ष और CEO जेमी डिमन और जनरल मोटर्स की अध्यक्ष और CEO मैरी बारा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। ये नेता प्रौद्योगिकी से लेकर वित्त और ऑटोमोटिव उद्योग तक, विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Key Points:-

(i) इस सूची में चार भारतीय मूल के नेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन और वर्टेक्स फार्मास्युटिकल्स की CEO डॉ. रेशमा केवलरमानी शामिल हैं। इनका समावेश प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों में भारतीय प्रतिभाओं की महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति को रेखांकित करता है।

(ii) फॉर्च्यून 100 की सूची में भी महिला नेताओं की मज़बूत उपस्थिति है, जिसमें 19 महिलाएँ शामिल हैं। इनमें एक्सेंचर की अध्यक्ष और CEO जूली स्वीट (रैंक 11), सिटीग्रुप की CEO जेन फ्रेजर (रैंक 12), AMD की अध्यक्ष और CEO लिसा सू (रैंक 14), और बैंको सैंटेंडर की कार्यकारी अध्यक्ष एना बोटिन (रैंक 20) शामिल हैं। इनका नेतृत्व प्रौद्योगिकी, वित्त और परामर्श जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है।

(iii) फॉर्च्यून की 100 सबसे शक्तिशाली व्यावसायिक लोगों की सूची एक प्रभावशाली मानक के रूप में कार्य करती है जो विभिन्न उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में प्रभावशाली नेतृत्व का सम्मान करती है। 2025 का संस्करण वैश्विक व्यावसायिक नेतृत्व में गतिशील बदलावों को दर्शाता है, जिसमें प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार, विविध प्रतिनिधित्व और विश्व मंच पर भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती भूमिका पर ज़ोर दिया गया है।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. एम.एस.स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

7 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीएआर पूसा, नई दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। "सदाबहार क्रांतिः जैव-सुख का मार्ग" विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में भारत की हरित क्रांति के अग्रदूत और सतत कृषि के वैश्विक समर्थक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती मनाई गई।

- **उद्घाटन सत्र के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेसर स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी व्यक्ति बताया, जिनका योगदान किसी भी युग से परे था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वामीनाथन ने विज्ञान को जनसेवा के माध्यम में बदल दिया और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।**

- **इस सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों ने सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और कृषि में नवाचारों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कृषि पर स्वामीनाथन के स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डाला और किसानों को सशक्त बनाने तथा कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।**

• अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन ने एक ऐसी चेतना जागृत की जो आने वाली सदियों तक भारत की नीतियों और प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार ने किसानों की शक्ति को राष्ट्र की प्रगति का आधार माना है।

Key Points:-

(i) प्रधानमंत्री ने खाद्य एवं शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की भी घोषणा की, जो विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और जलवायु न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया वैश्विक सम्मान है। यह पुरस्कार दुनिया भर में स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में स्वामीनाथन की स्थायी विरासत को दर्शाता है।

(ii) शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेसर स्वामीनाथन के सम्मान में भारत सरकार द्वारा जारी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। ये डाक टिकट भारत के कृषि परिदृश्य में उनके अमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप हैं।

(iii) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के सहयोग से एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF द्वारा आयोजित इस सम्मेलन ने 'सदाबहार क्रांति' के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और कृषि में सतत और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया।

IMPORTANT DAYS

1. भारत 7 अगस्त 2025 को 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जिसका विषय है "नवाचार को परंपरा में बुनना"।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा बुनकर समुदाय के सम्मान और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाता है। 2025 में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की थीम "नवाचार को परंपरा में बुनना" है, जो इस क्षेत्र की विरासत और आधुनिकता के मिश्रण को दर्शाता है।

• राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन पहली बार 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु के शताब्दी हॉल में किया था। यह दिवस भारत की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत में हथकरघा बुनकरों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करता है।

• यह दिन स्वदेशी आंदोलन को श्रद्धांजलि देता है, स्वदेशी उत्पादों के महत्व और पूरे भारत में आत्मनिर्भरता और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में हथकरघा की भूमिका पर जोर देता है।

• 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का विषय, "परंपरा में नवाचार बुनाई", उद्योग को जीवंत और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए पारंपरिक बुनाई प्रथाओं के साथ आधुनिक तकनीकों और डिजाइनों के एकीकरण का जश्न मनाता है।

Key Points:-

(i) हथकरघा क्षेत्र भारत में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, जो लाखों लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण

क्षेत्रों में, आजीविका प्रदान करता है तथा भारत के वस्त्र निर्यात और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

(ii) राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, सतत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।

(iii) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (NHDC) हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने में विपणन, उत्पादन और हथकरघा बुनकरों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे इस पारंपरिक उद्योग को बनाए रखने और विकसित करने में मदद मिलती है।

BOOKS & AUTHORS

1. एम.एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती के अवसर पर जीवनी 'द मैन हू फेड इंडिया' का विमोचन किया गया।

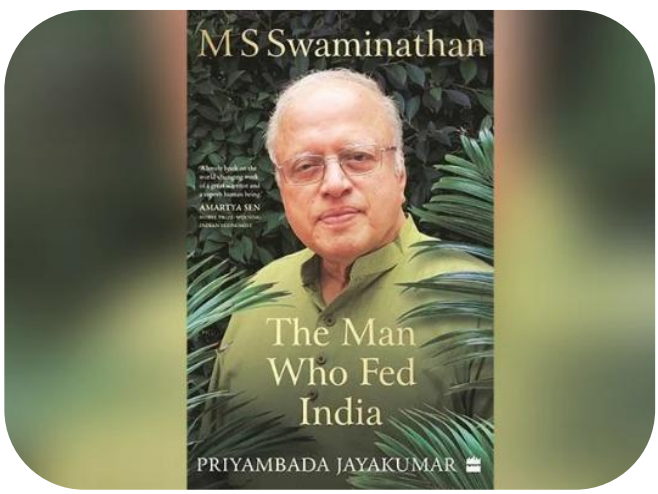

7 अगस्त, 2025 को, मनकोम्बु सम्बाशिवन स्वामीनाथन (एम.एस. स्वामीनाथन) की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में द मैन हू फेड इंडिया नामक जीवनी का विमोचन किया गया।

• हरित क्रांति के जनक के रूप में व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले स्वामीनाथन ने भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• यह जीवनी एम.एस. स्वामीनाथन का मानवीय चित्रण प्रस्तुत करती है, जिसमें उनके प्रारंभिक जीवन, वैज्ञानिक करियर, नीति-निर्धारक भूमिकाओं और उनके मार्गदर्शक व्यक्तिगत दर्शन से जुड़े दुर्लभ किस्से, व्यक्तिगत उद्धरण और महत्वपूर्ण क्षण शामिल हैं। यह गहन अंतर्दृष्टि पाठकों को भारत के कृषि परिवर्तन के पीछे के व्यक्ति से जुड़ने में मदद करती है।

Key Points:-

(i) स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यह पुस्तक 1960 और 1970 के दशक में उच्च उपज वाली गेहूँ और चावल की किस्मों को विकसित करने के उनके अग्रणी प्रयासों पर प्रकाश डालती है, जिससे खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली।

(ii) हरित क्रांति से आगे बढ़कर, स्वामीनाथन ने "सदाबहार क्रांति" की अवधारणा गढ़ी, जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य से समझौता किए बिना दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से टिकाऊ, समावेशी और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों पर जोर देती है।

(iii) शताब्दी समारोह के दौरान जीवनी का विमोचन स्वामीनाथन की स्थायी विरासत और भारत के कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा में उनके अपार योगदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है, जो भावी पीढ़ियों को टिकाऊ कृषि नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

ENVIRONMENT

1. मिजोरम में नया संकीर्ण-पट्टी वाला वर्षा साँप स्मिथोफिस लेप्टोफैसिआटस खोजा गया, जिससे

स्मिथोफिस वंश का विस्तार पांच प्रजातियों तक हो गया।

अगस्त 2025 में, मिज़ोरम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण समूह हेल्प अर्थ के साथ मिलकर मिज़ोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफैसिआटस नामक संकरी पट्टियों वाले बरसाती साँप की एक नई प्रजाति की खोज की। यह खोज, जो टैप्रोबैनिका: द जर्नल ऑफ़ एशियन बायोडायवर्सिटी में प्रकाशित हुई है, स्मिथोफिस वंश की ज्ञात प्रजातियों की कुल संख्या को बढ़ाकर पाँच कर देती है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सरीसृप विविधता को उजागर करती है।

• नए पहचाने गए साँप, स्मिथोफिस लेप्टोफैसिआटस, दिखने में अलग है क्योंकि इसका चमकदार काला शरीर संकरी, अधूरी अनुप्रस्थ पट्टियों से चिह्नित है जिनका रंग क्रीमी-सफ़ेद से लेकर पीले-नींबू के रंग तक होता है। ये अनोखे निशान इसे स्मिथोफिस वंश की अन्य प्रजातियों से अलग करते हैं।

• यह प्रजाति मिज़ोरम के 900 से 1,200 मीटर की ऊँचाई वाले ऊंचे पर्वतीय जंगलों में पाई जाती है। यह नदियों और घने पत्तों वाले इलाकों को पसंद करती है और अर्ध-जलीय तथा रात्रिचर जीवनशैली के लिए अच्छी तरह अनुकूलित है। इसका आवास चयन इस क्षेत्र में इसके पारिस्थितिक स्थान को दर्शाता है।

• स्मिथोफिस लेप्टोफैसिआटस का आहार मुख्य रूप से केंचुए होते हैं, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका को बनाए रखते हैं। बंदी अवलोकनों में एक गर्भवती मादा को छह चमड़े जैसे अंडे देते हुए देखा गया, जिससे इसके प्रजनन जीव विज्ञान के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली।

Key Points:-

(i) पहले, स्मिथोफिस लेप्टोफैसिआटस को स्मिथोफिस बाइकलर की निकट संबंधी प्रजाति समझ लिया जाता था। हालाँकि, आनुवंशिक विश्लेषण के माध्यम से, शोधकर्ताओं ने एक अनोखी प्रजाति के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि की, जिससे आधुनिक वर्गीकरण में आणविक तकनीकों के महत्व पर ज़ोर दिया गया।

(ii) यह खोज मिज़ोरम में दर्ज स्मिथोफिस वंश की तीसरी प्रजाति है, जो स्मिथोफिस एटमपोरेलिस और स्मिथोफिस मिज़ोरामेंसिस के बाद है। यह जैव विविधता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में मिज़ोरम के महत्व और इस क्षेत्र में निरंतर संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को और भी रेखांकित करता है।

Static GK

Russia	प्रधान मंत्री: मिखाइल मिशुस्टिन	राजधानी: मास्को
Federation of Indian Export Organizations (FIEO)	महानिदेशक (डीजी) और सीईओ: डॉ.अजय सहाय	मुख्यालय: नई दिल्ली
Illinois	राजधानी: स्प्रिंगफील्ड	गवर्नर: जेबी प्रित्जकर
NITI Aayog	सीईओ: बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम	मुख्यालय: नई दिल्ली
RBI	गवर्नर: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: नई दिल्ली
Goldman Sachs Group, Inc.	अध्यक्ष एवं CEO : डेविड माइकल सोलोमन	मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
Fortune Magazine	CEO : अनास्तासिया न्यर्कोव्स्काया	मुख्यालय : न्यूयॉर्क, अमेरिका
the National Handloom Development Corporation (NHDC)	अध्यक्ष : डॉ. एम. बीना	मुख्यालय : उत्तर प्रदेश, भारत